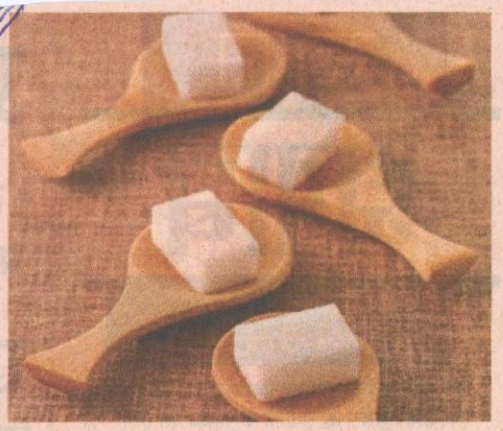

शुगर प्रॉडक्शन के अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर सकता है महाराष्ट्र

[जयश्री भोसले | पुणे]

केंद्र सरकार मंगलवार को देश में शुगर प्रॉडक्शन और स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने जा रही है, ऐसे में महाराष्ट्र अपने शुरुआती एस्टिमेट के मुकाबले राज्य के शुगर प्रॉडक्शन में करीब 10 फीसदी का गिरावट का अनुमान जता सकता है। होलसेल (थोक) में चीनी की कीमतें 40 रुपये/ किलो के लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जिसने पांच राज्यों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।

2016-17 के पेराई सीजन की शुरुआत में महाराष्ट्र करीब 50 लाख टन शुगर प्रॉडक्शन की उम्मीद कर रहा था। हालांकि, राज्य में लगातार तीन साल सूखा पड़ने, पिछले साल जून और जुलाई में पर्याप्त बारिश न होने का फसल पर इतना प्रतिकूल असर पड़ा कि पेराई ऑपरेशंस शुरू होने के बाद ही यह स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा। सरकार से जुड़े एक उच्च स्तरीय सूत्र ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'प्रति एकड़ यील्ड पर प्रतिकूल असर पड़ा है।' राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही प्रॉडक्शन और स्टॉक की स्थिति का आकलन किया है। राज्य की शुगर इंडस्ट्री में काम करने वाले एक दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'हमारा मानना है कि राज्य का शुगर प्रॉडक्शन घटकर 45 लाख टन रह सकता है।' 20 जनवरी तक राज्य की शुगर मिलों ने 32.72 लाख टन शुगर का प्रॉडक्शन किया था, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 फीसदी कम है। एक पखवाड़े पहले चीनी की कीमतों में तेजी का रुझान शुरू हुआ था और इसके बाद होलसेल में इसके दाम 40 रुपये प्रति किलो को पार कर गए। केंद्र सरकार ने शुगर मिलों को चेताया था कि वह आगामी विधानसभा चुनावों पर ध्यान दिए बगैर कोई भी कदम उठा सकती है। इसके बदले में, प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने अपने मेंबर्स को लेटर लिखकर किसी भी तरह की कयासबाजी से जुड़ी गतिविधि में शामिल न होने को कहा। सरकार की तरफ से बढ़ते दबाव के कारण मुंबई में पिछले हफ्ते चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहीं। महाराष्ट्र में प्रॉडक्शन में करीब 5 लाख टन की गिरावट आने का डर है। वहीं, ISMA का दावा है कि करेंट सीजन के पहले तीन महीनों के दौरान देश में शुगर सेल्स 5.5 लाख टन घटी है। ISMA करेंट सीजन के लिए शुगर प्रॉडक्शन का अपना दूसरा एडवांस एस्टिमेट 25 जनवरी को रिलीज करेगा।

होलसेल में चीनी की कीमतें 40 रुपये/ किलो के लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जिसने पांच राज्यों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।

The Economic Times (Hindi)
24/1/17